Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, JULY-AUG, 2018, VOL- 6/46

CNBC आवाज़ पर विमुद्रीकरण की खबरों का प्रस्तुतिकरण

धरवेश कठेरिया[1], अविनाश त्रिपाठी[2], नीरज कुमार सिंह[3], पदमा वर्मा[4] & अनुराधा[5]

1- सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र।

2- 4, एम. फिल. शोधार्थी, जनसंचार विभाग (2016-17), महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र।

3- एम. फिल. शोधार्थी, सामाजिक वहिष्करण एवं समावेशी नीति अध्ययन केंद्र (2016-17), काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तरप्रदेश।

5- शोधार्थी एम. ए., जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र।

Abstract

देश की अर्थव्यवस्था उसके मुद्रा संचरण की स्थिति पर निर्भर करती है। बाज़ार में मुद्राओं का प्रसार जितना बेहतर तरीके से होगा, अर्थव्यवस्था की विकास दर भी उतना ही अच्छी आँकी जा सकेगी। ये मुद्रा बैंकिंग प्रणाली से गुजरती हुई बाज़ार में प्रसारित होती है। जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और मुद्रा संचरण का प्रत्येक स्तर सरकार द्वारा निरीक्षण व नियंत्रित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग जो पूरी तरह से कैश अर्थव्यवस्था पर आश्रित थे उनके 500 और 1000 रुपए के नोट एक मात्र कागज का टुकड़ा बनकर रह गए थे। पूरे दिन सुबह से शाम तक लोग एटीएम और बैंकों के सामने लाइनों में खड़े रहे। आम लोग जिन्हें कुछ नहीं सूझता कि क्या करें? और ऊपर से सरकार के विमुद्रीकरण से संबन्धित एटीएम और बैंकों के लिए नए-नए नियम लोगों की परेशानियों को और अधिक बढ़ा रहे थे। ऐसे में सरकार के इन नए नियमों को जनता के समक्ष लाने और उनकी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने में CNBC आवाज़ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरबीआई के अनुसार देश में जाली/नकली नोटों के इस्तेमाल और आतंकवादी गतिविधियों की बढ़ती घटनाओं को रोकने हेतू इस तरह की घोषणा करना अनिवार्य था। CNBC आवाज़ ने देश की अर्थव्यवस्था और शेयर बाज़ार पर विमुद्रीकरण के प्रभाव के दोनों पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास किया है। बैंकों में पुराने नोट बदलने की प्रक्रिया 30 दिसम्बर, 2016 तक चलती रही। इस दौरान सरकार की गतिविधियों को आमजन तक पहुंचाने में CNBC आवाज़ ने प्राइम टाइम शो में मुख्य मुद्दा विमुद्रीकरण को रखा।

शब्द कुंजी: *CNBC आवाज़, प्राइम टाइम शो, आरबीआई, विमुद्रीकरण, मुद्रास्फीति, सूचकांक।*

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

उपकल्पनाः

- · विमुद्रीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई।
- विमुद्रीकरण की ख़बरों को CNBC आवाज़ ने सकारात्मक एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।
- CNBC आवाज़ ने विमुद्रीकरण के प्रति आमजन में जागरुकता बढ़ाई।
- विमुद्रीकरण से कालेधन पर लगाम लगी और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला।

उद्देश्यः

अध्ययन को स्वरूप प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य तय किए गए हैं जो इस प्रकार है-

- · विमुद्रीकरण के दौरान उत्पन्न सामाजिक असंतुलन एवं जागरुकता का अध्ययन करना।
- CNBC आवाज़ पर प्रसारित विमुद्रीकरण के दौरान ख़बरों की प्रस्तुतिकरण का अध्ययन करना।
- विमुद्रीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव एवं मीडिया प्रस्तुति का अध्ययन करना।

शोध सीमाएं:

शोध अध्ययन में 'CNBC आवाज़' चैनल पर प्रसारित विमुद्रीकरण से संबन्धित प्राइम टाइम विडियो को शामिल किया गया है। CNBC आवाज़ के प्राइम टाइम (रात्री 7.57) में प्रसारित कार्यक्रम 'आवाज़ अड्डा' में 8 नवंबर, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद विमुद्रीकरण विषय पर प्रसारित किए गए कार्यक्रम 'आवाज़ अड्डा' आरंभ के 5 विडियो

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

को लिया गया है। शोध की सीमाओं में 08 नवम्बर, 2016 से 31 नवंबर 2016 तक के समयांतराल के महत्वपूर्ण समय को शामिल किया गया है।

साहित्य पुनरावलोकन:

प्रस्तुोत शोध कार्य विषय: 'CNBC आवाज़ पर विमुद्रीकरण की खबरों का प्रस्तुबतिकरण' को स्व रूप प्रदान करने के द्दष्टिकोण से प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोध लेख, रिपोर्ट एवं उपलब्ध अन्य साहित्य का अध्ययन किया गया है।

पुस्तक:

- सिंह, डॉ. सुदामा, और सिंह, डॉ. राजीव कृष्ण. (2011). भारतीय अर्थव्यवस्था. नई दिल्ली: राधा पब्लिकेशन्स.भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित पुस्तक प्राचीन समय से लेकर अब तक के भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़े स्पष्ट शब्दों में दर्शाता है। भारत में पूंजी निर्माण, राष्ट्रीय आय, वृद्धि, वितरण, विकास एवं संरचना का स्पष्ट शब्दों में व्याख्या करता है।
- Smith, Adam. (2005). An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nation. An Electronic Classics Series Publication

एडम स्मिथ ने प्रसिद्ध पुस्तक 'WEALTH OF NATIONS' में अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए लिखा है-"अर्थशास्त्र का संबंध राष्ट्रों के धन के स्वरुप एवं कारणों की खोज से संबंधित है।" (Economics is concerned with an enquiry into the nature and causes of wealth of nations) प्रस्तुत पुस्तक में अर्थव्यवस्था की शुरुआती दौर और उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है।

- Maddison, Angus. (2003). The World Economy: A Millennial Perspective, Development Centre of The Organisation for Economic Co–Operation and Development.

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

पुस्तक में पुरे विश्व के विकसित अर्थशास्त्र को संक्षेप में समझाने की कोशिश की गई है। 124 देशों के लिए प्रति व्यक्ति वार्षिक आय और सकल घरेलु उत्पाद को भी समझाया गया है।

शोध पत्रिका-

- Lahiri, Ashok K (16 dec, 2016): "Demonetisation and Cash Shortage," The Economic and Political Weekly, Vol. 51, Issue No. 51. http://www.epw.in/journal/2016/51/web-exclusives/demonetisation-and-cash-shortage.html-0#sthash.CVAiGCCC.dpuf.
- शोध पत्रिका में "Demonetization and Cash Shortage" शीर्षक में बताया गया कि 500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद यह परिणाम निकला कि बाजार में नोटों की संख्या में कमी आयी है, इस पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- Ramdurg, Anil I, CS, Basavaraj (dec. 2016): "Demonetization: Redefining Indian economy," International Journal of Commerce and Management Research, Volume 2, Issue 12, Page No. 07-12

विमुद्रीकरण सरकार के द्वारा लिया गया एक बहुत बड़ा कदम है खासकर उन समस्याओं के उन्मूलन के लिए जैसे- कालाधन, नकली नोट, भ्रष्टाचार और आतंकवाद आदि तथ्यों पर केंद्रित है।

शोध आलेख-

- Patnaik, Prabhat (16 nov, 2016): "Black Money' and India's Demonetization Project," Global Research center for research on globalization.(http://www.globalresearch.ca/black-money-and-indias-demonetization-project/5557384)

Centre for Research on Globalization' एक स्वतंत्र शोध और मीडिया संगठन है। यह क्यूबेक, कनाडा के प्रांत में एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संस्था है। यह आलेख भारत

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

में विमुद्रीकरण और कालेधन के संबंध एवं अर्थव्यवस्था की स्थिति से हमें अवगत कराता है।

• एजेंसी, मुंबई (14 dec, 2016): "नोटबंदीः 8 नवंबर, के बाद से आरबीआई ने जारी किए 4.61 लाख करोड़ के नए नोट," इंडिया न्यूज़, नेशनल (http://www.amarujala.com/india-news/rbi-asked-banks-to-secure-the-cctv-recording)

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नोटबंदी को लागू किए 35 दिन बीतने को हैं। पुराने नोट जमा करने में अब भी 16 दिन का समय शेष है और प्रधानमंत्री मोदी के वादे में मात्र 15 दिन का समय है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या शेष 15 दिनों में हालात सामान्य हो पाएंगे?

शोध प्रबंध-

• Nath, Pranjit Kumar (30 june, 1998). Impact of inflation on corporate financial statements (Doctoral dissertation, Gauhati University). Retrieved from http://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/67015

थीसिस में प्रंजीत कुमार नाथ ने मुद्रास्फीति का कार्पोरेट जगत में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है और साथ ही वित्तीय विवरण का अध्ययन किया है। थोक मूल्य सूचकांक और क्रय शक्ति सूचकांक के विवरण को शामिल किया गया है।

• Sayira banu, N (2011). An analysis of the impact of economic reforms in India on selected macro economic variables (Doctoral dissertation, Madurai Kamraj University) Retrieved from http://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/132818

प्रस्तुत थीसिस में भारतीय अर्थव्यवस्था का वित्तीय निष्पादन, एफडीआई पर आर्थिक सुधारों का प्रभाव, विदेशी मुद्रा भंडार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अध्ययन किया गया है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

पत्रिका-

• गुप्ता, अखिल (18 jan, 2017): "नोटबंदी का अस्त्र," इंडिया टुडे, पेज नं. 35.

नोटबंदी पर प्रकाशित लेख में नोटबंदी को देश के लिए जरुरी बताया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में जीत के लिए यह एक सहज और सराहनीय हथियार है, का विस्तार से अध्ययन किया गया है।

• Debroy, Bibek (25 November 2016): "Demonetisation Demythified," open magazine,
http://www.openthemagazine.com/article/essay/demonetisation-demythified

'ओपन' मैगज़ीन राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, कला, सिनेमा और खेल पर लेखन के साथ एक साप्ताहिक भारतीय पत्रिका है। प्रस्तुत आलेख में विमुद्रीकरण के हर एक पहलू को गहराई से समझाने का प्रयास किया गया है। बिबेक देबरॉय एक सफल अर्थशास्त्री भी हैं।

रिपोर्ट-

• VISTRA, (1 Feb. 2017). India Report on Demonetisation (research report). https://www.vistra.com/insights/report-on-demonetisation

• रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 8 नवम्बर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट के विमुद्रीकरण की घोषणा की। यह कदम भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ एक बहुत बड़ी पहल थी।

• HDFC Bank Investment Advisory Group, (November 11, 2016). Demonetization and its impact (report).https://www.hdfcbank.com/assets/pdf/Event_Update_Demonetization_and_its_impact.pdf

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

रिपोर्ट में विमुद्रीकरण के बाद के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। 500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद उसका मूल्य 14.2 ट्रिलियन का हुआ जिसका 85% पूरे संचारित मुद्राओं का मूल्य है।

शोध प्रविधिः

प्रस्तुत अध्ययन विषय- 'CNBC आवाज़ पर विमुद्रीकरण की खबरों का प्रस्तुतिकरण' को स्वरूप प्रदान करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मवक विधियों का प्रयोग किया गया है। प्रविधि के माध्यम से विषय को एक निश्चित आकार दिया गया है। शोध को पूर्ण रूप देने के लिए शोध में प्रयुक्तप प्रविधि का विवरण इस प्रकार है जिनके प्रयोग के माध्यम से शोध को स्वरूप प्रदान किया गया है-

- · अवलोकन पद्धति: अध्ययन को मूर्त रूप देने के लिए उद्देश्यपरक अवलोकन के अंतर्गत CNBC आवाज़ के प्राइम टाइम में प्रसारित किए गए विमुद्रीकरण पर आधारित कार्यक्रम आवाज़ अड्डा का चयन किया गया है।
- · अंतर्वस्तु विश्लेषण: शोध अध्ययन में CNBC आवाज़ के प्राइम टाइम पर विमुद्रीकरण पर प्रसारित कार्यक्रम आवाज़ अड्डा को अंतर्वस्तु विश्लेषण हेतु चयन किया गया है।

प्रस्तावना:

भारतीय अर्थव्यवस्था में विमुद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो देश की आर्थिक स्थिति को सकारात्मक मजबूती प्रदान करता है। विमुद्रीकरण का इतिहास भारत के आजादी के पूर्व से ही स्थापित है। भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई के समय पहली बार जनवरी 1946 में 1000 और 10,000 रुपए के नोटों को विमुद्रीकरण के तहत वापस ले लिया गया अर्थात प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद 1954 में पुनः 1000, 5000 और 10,000 के नए नोट शुरू किए गए थे। स्वतन्त्रता के पश्चात भारत में विमुद्रीकरण का नया इतिहास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा 8 नवम्बर, की रात लिखा गया।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

8 नवम्बर, 2016 की रात 8 बजे 500 और 1000 रूपये के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा की गई। टीवी चैनलों पर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए राष्ट्र के संबोधन से आमजन को यह सूचना प्राप्त हुई। घोषणा के अनुसार 8 नवम्बर, 2016 की आधी रात 12 बजे के बाद से देश में 500 और 1000 रुपये के नोट चलन से बाहर हो गए। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य कालेधन पर नियंत्रण, जाली नोटों पर प्रतिबंध, आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों को ख़त्म करना था। छः महीने पहले से ही बननी शुरू हो चुकी इस योजना की जानकारी केवल कुछ सरकारी लोगों तक ही सीमित रखी गई।

अचानक लिए गए इस फैसले से बाजार पूरी तरह ठप्प हो गया था, आम जनता एवं छोटे व्यापारियों पर इसका बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा परंतु यह थोड़े समय के लिए हानिकारक तथा लंबे समय बाद के लिए लाभदायक रहा।

28 अक्टूबर, 2016 तक देश में कुल 17.77 लाख करोड़ (यूएस $260 बिलियन) पुरानी मुद्रा प्रसार में थी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश में 31 मार्च, 2016 में प्रचलित पुराने नोटों की कुल कीमत 16.42 लाख करोड़ (यूएस $240 बिलियन) थी जिसमें से 86% (14.18 लाख करोड़ (यूएस $210 बिलियन)) 500 और 1000 के पुराने नोट शामिल हैं। विमुद्रीकरण के बाद आम जन-जीवन को सचेत करने एवं पल-पल की खबर देने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही है मीडिया ने न केवल लोगों को जागरूक किया वरन सरकार और आम जनता के बीच की खाई को भरने एवं आपसी संबंध को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस संबंध में CNBC आवाज़ के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए शीर्षक 'CNBC आवाज़ पर विमुद्रीकरण की खबरों का प्रस्तुतिकरण' किया गया है। CNBC आवाज़ भारत का एक बिजनेस टीवी चैनल है जो बाजार से संबन्धित खबरें प्रसारित करता है। यह मुख्य रूप से व्यापार, वाणिज्य और वित्त संबन्धित खबरों को स्थान देता है। भारत में CNBC आवाज़ अमेरिका के CNBC चैनल का ही उपक्रम है। चैनल के स्वामित्व का अधिकार कॉमकास्ट के अंतर्गत है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

इसका मुख्यालय एंगलवुड क्लिप्स, न्यू जर्सी में है। यह इन्टरनेट, सेटेलाइट और केबल आधारित बिजनेस न्यूज़ टेलीविजन चैनल है जो एनबीसी यूनिवर्सल न्यूज़ ग्रुप द्वारा संचालित किया जा रहा है जो कि एनबीसी यूनिवर्सल का ही एक हिस्सा है।

तथ्य विश्लेषण एवं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरणः

प्रस्तुत विषय "CNBC आवाज़ पर विमुद्रीकरण की खबरों का प्रस्तुतिकरण" में CNBC आवाज़ (बाजार समाचार चैनल) पर प्रसारित दिनांक 8 नवंबर, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 के मध्य प्राइम टाइम के समय (आवाज़ अड्डा कार्यक्रम) में विमुद्रीकरण से संबंधित प्रसारित कुल 5 कार्यक्रमों को शोध अध्ययन हेतु शामिल किया गया है। आवाज़ अड्डा कार्यक्रम CNBC आवाज़ चैनल की प्राइम टाइम का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो चैनल में हर दिन शाम 7:57 पर प्रसारित होता है जो आम जनता को विमुद्रीकरण के सच्चाई से अवगत कराता है। नोटबंदी के समय में प्रसारित किए गए प्राइम टाइम कार्यक्रम, समाचार चैनल की वेबसाईट पर सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण इन कार्यक्रमों को यूट्यूब से अध्ययन हेतु लिया गया है जिनका यूट्यूब लिंक नीचे दिया गया है। इनमें विषय विशेषज्ञों में मार्केट एक्सपर्ट, टैक्स एक्सपर्ट, अर्थव्यवस्था एवं वित्त संबंधी विशेष जानकार और पक्ष एवं विपक्ष के राष्ट्रीय नेताओं को सम्मिलित किया गया है।

वीडियो क्रमांक – 01

कार्यक्रम का शीर्षक – आवाज़ अड्डा : नोट बैन – निकलेगा कालाधन

https://www.youtube.com/watch?v=HT1kjO7D6wQ

यूट्यूब पर अपलोड दिनांक – 10 Nov, 2016

क्रमांक	विषय विवरण	
1.	प्रसारण में प्रस्तुत विषय	नोटबैन – निकलेगा कालाधन
2.	प्रस्तुतकर्ता/एंकर	तमन्ना इनामदार दत्ता
3.	कार्यक्रम की अवधि/ कार्यक्रम प्रारूप	56:23, पैनल डिस्कशन / चर्चा

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

4.	**पैनल में सम्मिलित लोग**	
	i. **जी वी एल नरसिम्हा राव (भाजपा प्रवक्ता)**	कालेधन पर सर्जिकल स्ट्राइक देश की बहुत बड़ी अघोषित राशि पर प्रहार है। (पक्ष)
	ii. **मुकेश नायक (कांग्रेस प्रवक्ता)**	लोगों की परेशानियों का जिक्र करते हुए देश में हो रहे 40 हजार शादियां और गाँवों में बैंकों के कमी पर प्रकाश डाला। (विपक्ष)
	iii. **संजीव मिश्रा (सपा प्रवक्ता)**	इनका सुझाव रहा कि नोटबंदी से 3 दिन पहले एटीएम से 100-100 के नोट निकलने चाहिए थे। (विपक्ष)
	iv. **टी पी ओस्तवाल (इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट)**	जब तक टैक्स की दरें नहीं घटेगी तब तक कालाधन खत्म करने की चेष्टा पूरी नहीं हो सकती। (सामान्य)
	v. **मोनिका हालन (मिंट की कंसल्टिंग एडिटर)**	कालेधन, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नोटबंदी का यह फैसला सुगम है। (पक्ष)
	vi. **अनिल बोकिल (अर्थक्रांति संस्थान, एनजीओ)**	इन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि सभी टैक्स खत्म कर दो, कालाधन भी समाप्त हो जाएगा। सिर्फ एक टैक्स लगाओ 'बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स' जिसमें बैंक से ऑटोमेटिक टैक्स कटेगा। (सामान्य)
	vii. **प्रो॰ जगदीप चोकर (ADR फाउंडर)**	इनका कहना है कि सरकार का यह फैसला गोपनीय नहीं था। 27 अक्टूबर, 2016 को दैनिक जागरण में खबर छपी थी कि 2000 रु के नोट आने वाले हैं। (सामान्य)
	viii. **अभय दुबे (वरिष्ठ पत्रकार)**	अभय दुबे ने कहा कि इस फैसले के बाद कालाधन और दोगुने तरीके से जेनरेट होगा। (असहमत)

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

5.	**निर्ष्कष**	पूरे चर्चा के अंत में एंकर तमन्ना ने यह कहते हुए समाप्त किया कि सरकार का यह कदम सराहनीय है। इसका मतलब साफ है कि यह चर्चा लगभग विमुद्रीकरण के पक्ष में रही।

विश्लेषण:

प्रस्तुत वीडियो के अनुसार इस पूरे चर्चा के अंत में CNBC आवाज़ की एंकर तमन्ना ने यह कहते हुए कार्यक्रम को समाप्त किया कि सरकार का यह कदम सराहनीय है।

वीडियो क्रमांक – 02

कार्यक्रम का शीर्षक – आवाज़ अड्डा: कैसी अर्थनीति कैसी राजनीति?

https://www.youtube.com/watch?v=imqRX08BvGE

यूट्यूब चैनल पर प्रसारण दिनांक – 14 नवंबर, 2016

क्रमांक	**विषय विवरण**	
1.	**प्रसारण में प्रस्तुत विषय**	**कैसी अर्थनीति कैसी राजनीति ?**
2.	**प्रस्तुतकर्ता/एंकर**	**तमन्ना इनामदार दत्ता**
3.	**कार्यक्रम की अवधि/ कार्यक्रम प्रारूप**	**54:06/ पैनल डिस्कशन/ चर्चा**
4.	**पैनल में सम्मिलित लोग**	
	i. राघव चड्डा (नेता, आप)	इस निर्णय का प्रभाव केवल मध्यम वर्ग के लोगों जैसे किसान, गृहिणी, कारपेंटर, मजदूरों पर अधिक पड़ा है, कोई धन्ना सेठ लाइन में नहीं खड़ा है। (विपक्ष)
	ii. चरनजीत सापरा (नेता, कांग्रेस)	सवा सौ करोड़ जनता के लिए जब कोई निर्णय लिया जाए तो उसके पूर्व नियोजन होना चाहिए। सरकार ने आनन-फानन में यह निर्णय लिया। (विपक्ष)

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

	iii.	**ज़फर इस्लाम (प्रवक्ता, बीजेपी)**	नोटबंदी को राजनीति से नहीं जोड़ें। हमारा मकसद देश का विकास करना है। (पक्ष)
	iv.	**मोहनदास पई (चेयरमैन, मनिपल ग्लोबल एजुकेशन)**	नोटबंदी के 5 दिन बाद 14,20,000 करोड़ में से 3,20,000 करोड़ रुपए बैंक में आ गया है जो कि सकारात्मकता को दर्शाता है। (सहमत)
	v.	**राजेंद्र तिवारी (वरिष्ठ पत्रकार)**	इन्होंने इस कदम की सराहना की है परंतु लाइनों में लगे लोगों के मौतों पर सवाल उठाया है। (सामान्य)
	vi.	**सीएम वासुदेव (पूर्व वित्त सचिव)**	सरकार थोड़ा अच्छा प्रबंध करके इस फैसले को लागू करती तो और ज्यादा लाभ मिल सकता था। (सहमत)
	vii.	**हर्षवर्धन त्रिपाठी (वरिष्ठ पत्रकार)**	इन्होंने सारे राजनीतिक पार्टियों पर तीखा प्रहार किया। बीजेपी से लेकर आप नेता अरविंद केजरीवाल, टीएमसी के नेता ममता बनर्जी, कांग्रेस जैसे सभी पार्टियों को नोट और वोट का रिश्ता बताया। (कटाक्ष/सहमति)
5.		**निर्ष्कष**	इस चर्चा से कुल मिलाकर यही निकलता है कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियां नोटबंदी के आड़ में अपनी राजनीति करना चाहती है। चैनल में पूछे गए सवाल से यह स्पष्ट होता है कि आधे से अधिक जनता सरकार के समर्थन में है।

विश्लेषण:

प्रस्तुत वीडियो के अनुसार राघव चड्ढा ने बताया कि आप आदमी पार्टी की फंडिंग पूरी तरह बैंकिंग प्रणाली के तहत होती है। कोई भी कैश में नहीं होता। राजेंद्र तिवारी जी ने कहा कि एग्रीकल्चर इन्कम है उस पर टैक्स लगे, इससे मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि किसानों का सारा फसल राम भरोसे यानि मौसम के ऊपर निर्भर करता है जिस पर

तमन्ना ने कहा कि जो किसान 80 करोड़, 30 करोड़ की एग्रीकल्चर इन्कम करते हैं और एक पैसा टैक्स नहीं देते उनके लिए नियम होने चाहिए।

चैनल में पूछे गए सवाल- "क्या नोटबंदी का राजनीतिक फायदा बीजेपी को होगा?" इस पर 72% जनता ने CNBC आवाज़ के ट्विटर पोल पर ट्वीट कर जवाब दिया कि नोटबंदी के फैसले से बीजेपी को फायदा होगा। जबकि 28% लोगों ने नहीं के पक्ष में जवाब दिया।

वीडियो क्रमांक – 03

कार्यक्रम का शीर्षक – आवाज़ अड्डा: नोटबंदी पर सियासी संग्राम

https://www.youtube.com/watch?v=Fm70e2QvOaU

यूट्यूब चैनल पर प्रसारण दिनांक – 16 नवंबर, 2016

क्रमांक	विषय विवरण	
1.	**प्रसारण में प्रस्तुत विषय**	**नोटबंदी पर सियासी संग्राम**
2.	**प्रस्तुतकर्ता/एंकर**	**तमन्ना इनामदार दत्ता**
3.	**कार्यक्रम की अवधि/ कार्यक्रम प्रारूप**	**55:21/ पैनल डिस्कशन / चर्चा**
4.	**पैनल में सम्मिलित लोग**	
	i. ज़फर इस्लाम (प्रवक्ता, बीजेपी)	इनका कहना है कि चाँदनी चौक के इलाके में बैंकों के सामने लाइन में लगे लोगों से उनकी परेशानियाँ पूछी गई तो उन्होंने बार-बार यही कहा कि हमें तकलीफ है पर हम मोदी जी के इस फैसले के साथ हैं। क्योंकि ऐसा साहस भरा फैसला कोई और प्रधानमंत्री नहीं ले सकता। ये तक़लीफ तो कुछ ही दिन की बात है। (पक्ष)

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

	ii. **पी एल पुनिया (प्रवक्ता, कांग्रेस)**	इन्होंने कहा कि कालाधन रियल स्टेट, गोल्ड, बाहर देशों में, स्विस बैंकों में है। ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके चलते कई लोगों की मौत हो गई, क्या उनको वापस ला सकते हैं। जो किसान है, छोटे व्यापारी हैं, जो सब्जी-फल बेचने वाले हैं, जो कभी भी बैंकिंग प्रणाली से नहीं जुड़े हैं वे क्या करेंगे। (विपक्ष)
	iii. **कलिकेश नारायण सिंह देव (सांसद, बीजेडी)**	इन्होंने बताया कि परेशानी है पर कुछ हद तक समर्थन भी है, ये सोचकर कि भ्रष्ट लोगों और कालेधन जमा करने वालों की संपत्ति पकड़े जाएंगे। मेरे दल (बीजेडी दल) ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। पर इसके पीछे कोई तैयारी नहीं है। जो गाँव में हैं, जहां बहुत दूर-दूर तक बैंक नहीं है उनको बहुत तकलीफें उठानी पड़ी है। (विपक्ष)
	iv. **शरत प्रधान (वरिष्ठ पत्रकार)**	इन्होंने कहा कि देश के किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों को नोटबंदी के इस फैसले की कोई खबर नहीं थी। यहाँ तक के सरकार के करीबियों को भी नहीं। उस दिन टेलीविज़न पर बोलते हुए अमित शाह को सुना, उनका चेहरा भी उतरा हुआ था। (सामान्य)
	v. **हर्षवर्धन त्रिपाठी (वरिष्ठ पत्रकार)**	नरेंद्र मोदी का समर्थन बहुत बड़ा है। इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने उस जगह पर चोट कर दी है जिसको देश की जनता मई 2014 से सुनते आ रही है। जब सिस्टम

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

		का फ़्लो रुकता है तो रियल स्टेट में लगने वाले ब्लैकमनी भी व्हाइट मनी में आते हैं। (सहमत)
	vi. हिलाल अहमद (एसोसिएट प्रोफेसर, सीएसडीएस)	इन्होंने कहा कि फैसला तो सहीं किए परंतु क्रियान्वित कैसे करें, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। इस देश के संविधान में वित्तीय संकट को लेकर कई सारे विधान है उसको लेकर कोई बात नहीं की गई। (सामान्य)
5.	**निर्ष्कष**	अंतिम में एंकर तमन्ना जी ने यह कहते हुए बात समाप्त किया कि कब तक जनता सरकार का समर्थन देते रहेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है।

विश्लेषण:

प्रस्तुत वीडियो के अनुसार यूपी में ज्वेलर्स से खूब सोना खरीदा गया। बहुत जगह पर कैश जला दिया गया। एंकर तमन्ना जी का सवाल था कि इस फैसले का क्या मोदी सरकार को राजनीतिक नुकसान होगा, जिस पर ट्विटर पर 76% लोगों ने नहीं में जवाब दिया और 24% लोगों ने हाँ में दिया। अंतिम में एंकर तमन्ना जी ने यह कहते हुए बात को समाप्त किया कि कब तक जनता सरकार का समर्थन देते रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

वीडियो क्रमांक – 04

कार्यक्रम का शीर्षक – आवाज़ अड्डा: कब खतम होगा कैश का कन्फ़्यूसन

https://www.youtube.com/watch?v=UBPgftXczcc

यूट्यूब चैनल पर प्रसारण दिनांक – 18 नवंबर, 2016

क्रमांक	विषय विवरण	
1.	**प्रसारण में प्रस्तुत विषय**	**कब खतम होगा कैश का कन्फ़्यूजन?**
2.	**प्रस्तुतकर्ता/एंकर**	**तमन्ना इनामदार दत्ता**
3.	**कार्यक्रम की अवधि/ कार्यक्रम प्रारूप**	**56:10/ पैनल डिस्कशन/ चर्चा**
4.	**पैनल में सम्मिलित लोग**	
	i. **जी वी एल नरसिम्हा राव (प्रवक्ता, बीजेपी)**	सरकार लोगों की परेशानियों को आकलन करने के बाद पूरी ज़िम्मेदारी के साथ परिस्थितियों को देख-देख कर ही नोटबंदी के नियम बदल रही है। (पक्ष)
	ii. **प्रियंका चतुर्वेदी (प्रवक्ता, कांग्रेस)**	जो टैक्स रेड हुए हैं उसमें से 7,700 करोड़ रुपए ब्लैकमनी के रूप में हैं जिनमें से केवल 5% ही कैश रहा है। इस 5% कैश को लाने के लिए आपने देश के 80% जनता को लाइन में खड़ा कर दिया। (विपक्ष)
	iii. **आतिशी मर्लेना (प्रवक्ता, आप)**	सरकार ने ज़ीरो प्लानिंग के साथ इतना बड़ा कदम उठाया है। हर 12 घंटे में नई घोषणा करते हैं फिर नियम बदल देते हैं। (विपक्ष)
	iv. **सुखेंदु शेखर रॉय (नेता, TMC)**	ये तुगलक राज है जिसमें विमुद्रीकरण का फैसला कुछ अधिकारियों के साथ ही ले लिया गया। (विपक्ष)
	v. **रामकृपाल सिंह (वरिष्ठ पत्रकार)**	सब तारीफ़ कर रहे हैं इस कदम की। जनता का भविष्य अच्छा होने की उम्मीद है। गाँव में

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

		80% लोग इस कदम की सराहना कर रहे हैं। (सहमत)
	vi. **एम के वेणु (फाउंडिंग एडिटर, Thewire.in)**	सरकार 14 लाख करोड़ की जो करेंसी बदल रही है उसमें से 20-25% ब्लैकमनी हो सकता है जो कन्वर्ट नहीं होगा, ये पैसे बैंकों के पुन:पूंजीकरण (Recapitalization) के लिए इस्तेमाल हो सकता है। (सामान्य)
	vii. **हर्षवर्धन त्रिपाठी (वरिष्ठ पत्रकार)**	वित्त मंत्रालय के नोटबंदी के नियमों को लागू करने और बार-बार बदलने की योजना ठप्प रही है। (असहमत)
5.	**निर्ष्कष**	कार्यक्रम के सार में यही निकलता है कि विमुद्रीकरण की यह योजना सहीं है परंतु इसे लागू और कार्यान्वयन उचित तरीके से नहीं किया गया।

विश्लेषण:

प्रस्तुत वीडियो के अनुसार चैनल में पूछे गए सवाल "क्या नोटबंदी की सोच सही, लेकिन प्लानिंग गड़बड़ रही है?" इसमें 58% जनता ने हाँ में ट्विटर पर ट्वीट कर जवाब दिया जबकि 42% जनता ने नहीं में जवाब दिया है। सभी प्रमुख एक्सपर्ट की राय और सुझाव के अनुसार इस विडियो का सारांश यही निकलता है विमुद्रीकरण की योजना सहीं होने के बावजूद उसे उचित तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया गया।

वीडियो क्रमांक – 05

कार्यक्रम का शीर्षक – आवाज़ अड्डा: टैक्स चोरों को सज़ा या मज़ा?

https://www.youtube.com/watch?v=QNcbl0VXbMQ

यूट्यूब चैनल पर प्रसारण दिनांक – 25 नवंबर, 2016

क्रमांक	विषय विवरण		
1.	**प्रसारण में प्रस्तुत विषय**		**टैक्स चोरों को सज़ा या मज़ा?**
2.	**प्रस्तुतकर्ता/एंकर**		**तमन्ना इनामदार दत्ता**
3.	**कार्यक्रम की अवधि/ कार्यक्रम प्रारूप**		**53:13/ पैनल डिस्कशन/ चर्चा**
4.	**पैनल में सम्मिलित लोग**		
	i.	**सुजॉय कांटावाला (वकील)**	एक मौका है टैक्स छिपाने वालों के लिए कि आप आइये टैक्स भरिए और चैन की नींद सो जाइए। (सहमत)
	ii.	**नरेंद्र तनेजा (प्रवक्ता, बीजेपी)**	टैक्स चोरों को चैन की नींद नहीं सोने दिया जाएगा, यही सरकार की नीति है। (पक्ष)
	iii.	**संजीव मिश्रा (प्रवक्ता, एसपी)**	देश में लाइन में लगे जितने लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार के एक सदस्य को भारत सरकार में नौकरी दी जाए। (विपक्ष)
	iv.	**वेद जैन (टैक्स एक्सपर्ट)**	ये स्कीम टैक्स चोरों को छुट देने के लिए नहीं बनाई है बल्कि उस स्कीम को सख्त करने के लिए बनाई है। (सहमत)
	v.	**संजय झा (प्रवक्ता, कांग्रेस)**	कालेधन जमा करने वाले लोग अपने जेब में या घरों में पैसे नहीं रखते बजाय 5-6% कैश के अलावा। इन्होंने सरकार की नीति पर कटाक्ष किया। (विपक्ष एवं

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

		असहमत)
	vi. **शामिका रवि (सीनियर फ़ेलो, ब्रूकिंग्स इंडिया)**	इनका कहना है कि सरकार को आंकड़ों से संबन्धित एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। (सामान्य)
5.	**निर्ष्कष**	कार्यक्रम में सारी राजनीतिक पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करती रही। इस चर्चा में ठीक तरह से कुछ निकल कर नहीं आया। चैनल पर ट्विटर के माध्यम से पूछे गए प्रश्न पर जनता के जवाब के अनुसार 75% लोगों का कहना है कि सरकार टैक्स चोरों को मौका देकर आम लोगों से नाइंसाफी कर रही है।

विश्लेषण:

प्रस्तुत विडियो में टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन का कहना है कि एक तो देश में 50% लोगों के पास बैंक खाता नहीं है, यदि अभी 15 दिन में खोलना चाहे भी तो मुझे नहीं लगता कि बैंक के पास इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा। इस पर नरेंद्र तनेजा जी ने जवाब दिया कि इस हफ्ते के आंकड़ों में 71 करोड़ डेबिट कार्ड है। 8 नवंबर, के बाद से लाखों नए खाते खोले गए हैं। CNBC आवाज़ के ट्विटर पोल पर पूछे गए सवाल "टैक्स चोरों को एक और मौका, क्या आम लोगों से नाइंसाफी?" पर 75% जनता ने हाँ में जवाब दिया जबकि 25% जनता ने नहीं में जवाब दिया है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सम्पूर्ण विश्लेषण:

कार्यक्रम में शामिल विशेषज्ञों का विमुद्रीकरण फैसले पर मत के अनुसार वर्गीकरण (संख्या में)						
वीडियो क्रमांक	**पक्ष**	**विपक्ष**	**सहमत**	**असहमत**	**सामान्य**	**कुल संख्या**
01	**2**	**2**		**1**	**3**	**8**
02	**1**	**2**	**3**		**1**	**7**
03	**1**	**2**	**1**		**2**	**6**
04	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**	**7**
05	**1**	**2**	**2**		**1**	**6** ↓
कुल संख्या	**6**	**11**	**7**	**02**	**8** →	**34**

CNBC आवाज़ चैनल में प्रसारित प्राइम टाइम कार्यक्रम 'आवाज़ अड्डा' के कुल 5 वीडियो में कुल 34 विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। इनमें से 6 विशेषज्ञों ने पूर्णतः विमुद्रीकरण के पक्ष में अपने मत रखे जिनमें बीजेपी प्रवक्ता प्रमुख रूप से शामिल थे। 11 विशेषज्ञों ने विमुद्रीकरण के संबंध में पूरी तरह सरकार के विपक्ष में मत रखे जिनमें विपक्षी दल जैसे- कांग्रेस, आप, टीएमसी, बीएसपी के नेता शामिल थे। पैनल में 7 विशेषज्ञों ने सरकार के फैसले पर सहमति जताई और केवल 02 विशेषज्ञों ने असहमति जताई वहीं 8 विशेषज्ञों ने सरकार के इस फैसले पर सामान्य विचार रखे। शोध विश्लेषण के आधार पर CNBC आवाज़ में प्रसारित आवाज़ अड्डा कार्यक्रम के कुल 5 वीडियो पैनल में सम्मिलित 34 विशेषज्ञों में से केवल 02 विशेषज्ञों ने ही सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले पर असहमति व्यक्त की है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है की

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

पैनल में सम्मिलित ज्यादातर विशेषज्ञों ने विमुद्रीकरण के फैसले पर सरकार का समर्थन किया।

शोध निष्कर्ष:

'CNBC आवाज़ पर विमुद्रीकरण की खबरों का प्रस्तुतिकरण' शीर्षक पर आंकड़ों के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं-

1. भारत का कालाधन रियल स्टेट, गोल्ड एवं स्विस बैंकों में हैं जिस पर विमुद्रीकरण का कोई खास असर नहीं पड़ा जबकि गांवों में बसे देश की आम जनता का जन-जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ।

2. CNBC आवाज़ में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार देश में 140 लोगों की मौत कतारों में खड़े होने की वजह से हो गई जो कि विमुद्रीकरण के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। विपक्षी पार्टियों के अनुसार यह फैसला सहीं था परंतु क्रियान्वयन ठीक तरह से नहीं किया गया।

3. विमुद्रीकरण के नियमों में प्रति दिन बदलाव ही विमुद्रीकरण की तैयारी को नाकाम साबित कर रहा था।

4. आरबीआई (RBI) के रिपोर्ट के मुताबिक केवल 16,000 करोड़ रुपए के पुराने नोट ही बैंक में नहीं आए हैं जो

कुल मुद्रा का केवल 1 प्रतिशत है अर्थात 99% मुद्रा वापस आ चुकी है, जिसे विमुद्रीकरण की सफलता के रूप में

देखा जा रहा है।

5. विमुद्रीकरण ने देश में टैक्स चोरी, जाली नोट और आतंकवादी गतिविधियों पर तीखा प्रहार किया है।

6. विमुद्रीकरण के दौरान डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिला।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

7. CNBC आवाज़ चैनल के ट्विटर पोल पर नोटबंदी से संबन्धित सभी प्रश्नों पर जनता से पूछे गए सवाल में देश की आधे से अधिक जनता ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है।

शोध सुझाव:

'CNBC आवाज़ पर विमुद्रीकरण की खबरों का प्रस्तुतिकरण' पर आकड़ों द्वारा निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए हैं जो इस प्रकार है-

1. सवा सौ करोड़ जनता के लिए जब कोई निर्णय लिया जाए तो उसके पूर्व नियोजन होना आवश्यक है।
2. बैंक व एटीएम की लाइनों में खड़े लोगों में जिनकी मौतें हुई है, उनके परिवार को आर्थिक लाभ या नौकरी दी जाए।
3. तरह-तरह के टैक्स लगाने के बजाय एक ही टैक्स लगाया जाए जिसकी प्रक्रिया सरल व सुविधाजनक हो।
4. कुछ ही कालेधन को समाप्त करने हेतु भारत के आम आदमी को परेशान करना अनुचित है। विमुद्रीकरण के दौरान निम्न वर्ग के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए थी।
5. टैक्स चोरी से बचने के लिए इसकी प्रक्रिया सरल होनी चाहिए।
6. डिजिटल पेमेंट की प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाना चाहिए।

शोध की उपयोगिता:

प्रस्तुत शोध विषय 'CNBC आवाज़ पर विमुद्रीकरण की खबरों का प्रस्तुतिकरण' के माध्यम से विमुद्रीकरण के दौरान देश में आर्थिक उथल-पुथल और आम जनता की स्थिति पर ध्यान केन्द्रित करना है। समाज में अचानक बदलाव से आम जन-जीवन पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, समाज उसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। नोटबंदी का प्रहार भी इसी तरह से हुआ। शोध में यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि कालेधन को निकालने के इस तरीके में क्या जनता सरकार के साथ थी? क्या

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

वे इस परेशानी के लिए तैयार थे? सरकार ने अपने रणनीतियों में सिर्फ कालेधन को लक्ष्य करते हुए कुछ लोगों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया, जबकि उसमें आम जनता की परेशानियों का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लगाया गया। शोधकर्ताओं के साथ-साथ सरकार द्वारा भविष्य में बनाई जाने वाली नीतियों के लिए प्रस्तुत शोध दिशासूचक साबित होंगा।

भविष्य में शोध:

प्रस्तुत शोध में प्राप्त आकड़े भविष्य में होने वाले विषय से संबंधित अध्ययनों के लिए महत्वपूर्ण होगें। भावी शोधार्थियों के लिए यह शोध संबन्धित विषय के दायरे में कार्य करने के लिए सहायक होगा तथा सरकार द्वारा भविष्य में बनाई जाने वाली नीतियों के लिए दिशासूचक साबित होंगा। प्रस्तुत शोध में आमजन की परेशानियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जो इस तरह के किसी भी प्रकार के शोध के लिए सहायक सिद्ध होगा। विमुद्रीकरण के दौरान आमजन की भागीदारी और योगदान इस शोध का आधार है।

सहायक संदर्भ सूची:

रंगराजन सी. (2006), भारत की अर्थनीति नए आयाम: नई दिल्ली, राजपाल एंड संज पब्लिकेशन।

चन्द्र बिपिन, (2000), भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास , नई दिल्ली, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स।

डॉ. शर्मा रमाकांत, (2008), वित्तीय समावेशन, नई दिल्ली, मेधा बुक्स।

भट्टाचार्य सब्यसाची, (2007), आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन।

सिंह, डॉ. सुदामा, और सिंह, डॉ. राजीव कृष्ण (2011). भारतीय अर्थव्यवस्था. नई दिल्ली: राधा पब्लिकेशन्स।

झुनझुनवाला भरत, (2009), भारतीय अर्थव्यवस्था-समीक्षात्मक अध्ययन, दिल्ली, राजपाल।

रिपोर्ट:

PTI, (7 mar. 2017). Report on demonetisation impact next month:Parliamentarypanel (report)

Reserve Bank of India, (Mar. 10, 2017). Macroeconomic Impact of Demonetisation,APreliminaryAssessment (report)

टाटा (1997) , रतन, इकोनोमिक टाइम्स, मई 28।

आर्थिक सर्वेक्षण (1995), इंडियन इकोनोमिक सर्वे 1994-95, भारत सरकार, नई दिल्ली।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

बेवसाइट संदर्भः

http://www.jagran.com/editorial/apnibaat-notebandi-results-disappointing-16661673.html

https://khabar.ndtv.com/news/india/90-of-scrapped-notes-back-in-system-no-big-relief-for-common-man-1642611

https://en.wikipedia.org/wiki/CNBC

https://timesofindia.indiatimes.com/tv/channel/cnbc-awaaz/params/tvchannel/channelid-10000000000890000

http://hindi.moneycontrol.com/tv/

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies